political consensus on the passing of this Bill. On the advice of this Ministry Law Commission has now taken up a study for formulating requisite law for combating terrorism in the country.

नये राज्यों का सृजन

2725. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा हाल में कितने राज्यों का सृजन किया गया है और संविधान के अनुसार अनुमोदित किया गया है;

(ख) ऐसे राज्यों के नाम क्या-क्या है;

(ग) क्या इन प्रस्तावित राज्यों की राजधानियों की भी पहचान कर ली गई है;

(घ) नए राज्य बनाने के लिए सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) क्या सौराष्ट्र क्षेत्र को भी पृथक राज्य बनाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है; तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) सरकार ने हाल में किसी राज्य का पुर्नगठन नहीं किया है।

(घ) और (ङ) नए राज्यों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव समय-समय पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तथापि, सरकार राज्यों के किसी सामान्य पुनर्गठन पर कोई विचार नहीं कर रही है। इस समय, मौजूदा बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के लिए कार्रवाई की जा रही है ताकि वनांचल, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड/उत्तरांचल नए राज्यों का सृजन किया जा सके।

Assam-Arunachal Pradesh Boundary Dispute

2726. SHRI NABAM REBIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a long standing boundary dispute exists between Assam and Arunachal Pradesh;

(b) whether it is also a fact that the Assam Police and Forest Department are frequently encroaching upon Arunachal Land thereby subjecting innocent Arunachal people to inhuman torture and eviction;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the steps taken to resolve this long-standing vexed problem?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Arunachal Pradesh Government have complained about incidents of encroaching by the Assam Police and Assam Forest Department inside Arunachal Pradesh and eviction of Arunachal villagers.

Government of Assam have, however, informed that no encroachment in the territory of Arunachal Pradesh is being done by the Assam Police or Forest Department.

(d) Government has directed both the State Governments to maintain status quo and resolve the problem amicably. Bilateral negotiations at the level of Chief Ministers of both the State Government have taken place. A Joint Ministerial Committee has been constituted by the two State Governments to resolve the boundary dispute.

Government of Assam have informed that they have taken steps for revival and expeditious disposal of the title Suit No. 1/89 pending in the Hon'ble Supreme Court of India in connection with Assam-Arunachal Pradesh boundary dispute.

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम पदार्थों में आत्मनिर्भरता

2727. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में पेट्रोलियम तथा उससे संबंधित पदार्थों की मांग को पूरा करने के लिए स्वदेशी उत्पादन के साथ साथ आयात का सहारा भी लेना पड़ता है;